संवैधानिक व्याख्या के चार चरण

लेखक - चिंतन चंद्रचूड़ (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (राजव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

27 जनवरी, 2020

"न्यायपालिका अपनी क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी क्षमता के अनुरूप संविधान की व्याख्या करने लगी है।"

70 साल पहले 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान का अधिनियमन एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक प्रयोग था, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ 550 से अधिक रियासतों वाले क्षेत्र में संघवाद और एक गहरी असमान समाज में सामाजिक क्रांति थी। हालाँकि, यह संवैधानिक रूप-रेखा के मामले में समान रूप से एक अनूठी उपलब्धि थी। गणतंत्र दिवस, विशेष रूप से इस वर्ष, हमें संविधान के बारे में राजनीतिक प्रतियोगिताओं से एक कदम वापस लेने का अवसर प्रदान करता है और हमे मौका देता है कि हम विचार करे कि पिछले सात दशकों में अदालतों द्वारा मूल पाठ की व्याख्या कैसे की गई है।

पहला चरण, मूलपाठ

अपने प्रारंभिक वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधानवादी दृष्टिकोण अपनाया, जो संविधान में प्रयुक्त शब्दों के स्पष्ट अर्थ पर केंद्रित था। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) मामला प्रारंभिक निर्णयों में से एक था, जिसमें न्यायालय को भाग III के मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने का मौका मिला था।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने दावा किया कि निवारक निरोध कानून जिसके तहत् उन्हें हिरासत में लिया गया था, अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता का अधिकार), 21 (जीवन का अधिकार) और 22 (मनमाना गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण) के साथ असंगत था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये सभी अनुच्छेद पूरी तरह से अलग-अलग विषयों को कवर करते हैं और इसलिए एक साथ पढ़ने के बजाय अलग-अलग कोड के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

भारतीय संवैधानिक कानून में सबसे विवादास्पद प्रश्नों में से एक यह है कि क्या संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमाएँ हैं? विशेष रूप से मौलिक अधिकार पर। अपने शुरुआती वर्षों में, अदालत ने संविधान को शाब्दिक रूप से पढ़ा और यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसी कोई सीमाएँ नहीं थीं।

दूसरा चरण, संरचना

दूसरे चरण में, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या के अन्य तरीकों की खोज शुरू की। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के मामले में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि संविधान को संशोधित करने की संसद की शक्ति इसके 'बुनियादी ढाँचे' को बदलने के लिए विस्तारित नहीं हुई है। जब संसद ने संविधान में संशोधन करके इस फैसले को फिर से पलटने का प्रयास किया। तो अदालत ने संरचनात्मक प्रयास पर भरोसा करते हुए निर्णायक रूप से उस प्रयास को खारिज कर दिया।

इसके अलावा, कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले में एक संरचनावादी व्यक्ति के पक्ष में गोपालन दृष्टिकोण को भी स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। इस निर्णय के माध्यम से न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को दोहराया, जिससे यह फैसला मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों के लिये एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण बना।

व्याख्यात्मक कहानी के पहले दो चरणों के बीच जो आम था वह यह था कि संविधान की व्याख्या से जुड़े महत्त्वपूर्ण फैसले संवैधानिक पीठों (अदालत के पाँच या अधिक न्यायाधीशों को शामिल) को सौंपे गए थे। यह पूर्ववर्ती भ्रम की सीमित गुंजाइश थी, क्योंकि जिन मामलों को संविधान पीठों द्वारा तय किया गया था और जिन पर पुनर्विचार की माँग की गई थी, उन्हें बड़े संविधान पीठों के लिए संदर्भित किया गया था।

तीसरा चरण उदारवाद के रूप में

तीसरे चरण में, उच्चतम न्यायालय का व्याख्यात्मक दर्शन पहले से कहीं अधिक परिणामोन्मुख था। दो कारकों ने इस संस्थागत विफलता को कम कर दिया। सबसे पहला, अदालत की बदलती संरचना, जिसकी स्थापना आठ न्यायाधीशों के साथ शुरू

हुई, 31 की स्वीकृत शक्ति तक बढ़ी यह वर्तमान में 34 है। इसने दो या तीन न्यायाधीशों के पैनल में बैठना शुरू किया। दूसरा, न्यायालय ने अपनी भूमिका की एक निश्चित अवधारणा के आधार पर मामलों को तय करना शुरू कर दिया – (चाहे लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में या बाजार अर्थव्यवस्था के रक्षक के रूप में)।

कारणों को देने में विफलता ने न केवल कार्यप्रणाली की असंगति में योगदान दिया, बल्कि कानून में गंभीर सिद्धांतगत असंगति में भी योगदान दिया। इसे पंचायती बहुसंख्यकवाद के रूप में सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जा सकता है, विभिन्न पीठों ने न्यायालय की भूमिका के बारे में अपनी धारणा के आधार पर असंगत व्याख्यात्मक दृष्टिकोण अपनाएँ और उस निष्कर्ष पर पहुँचे जो अक्सर एक दूसरे के साथ तनाव में थे। पंचायती पारिस्थितिकीवाद को लागू करने के लिए जो कल्पना है, वह बुद्धिमान पुरुषों और महिलाओं के समूह (सादृश्य, उप-सुप्रीम कोर्ट) को लागू करने के लिए है, जो निष्पक्षता, सिद्धांत और स्थापित व्याख्यात्मक धारणाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं।

चौथा चरण, उद्देश्य

वर्तमान में हम संवैधानिक व्याख्या के तीसरे चरण से चौथे तक के संक्रमण के बीच में हैं। भारत का संविधान इसकी स्थापना के समय अलग था। संविधान लागू करने में हमारे गणतंत्र के संस्थापकों ने यथास्थिति के साथ असहमत होने की भावना व्यक्त की और सामाजिक क्रांति तथा परिवर्तन की उम्मीदें जगाई। न्यायालय अब अपनी क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी क्षमता के अनुसार संविधान की व्याख्या करने लगा है।

सितंबर 2018 से उच्चतम न्यायालय से लगभग एक दर्जन महत्त्वपूर्ण संविधान पीठों के फैसले लिए गये, जो संविधान पीठों द्वारा निर्णय लेने की घटना में एक पुनर्जागरण से कम नहीं था। इसमें धारा 377, व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाना और सूचना के अधिकार के दायरे में भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय सहित न्यायालय के फैसले शामिल हैं।

हालाँकि, तीसरा चरण के पहलू न्यायालयों में आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे मामले जिनमें संविधान की व्याख्या के पर्याप्त प्रश्न शामिल हैं – (जैसे कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और चुनावी बांड योजना से संबंधित मामले)। ये अभी भी दो या तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा स्थगित किए जा रहे हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है।
2. ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) मामले को न्यायालय ने भाग III से संबंधित बताया है।
3. केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य (1974) मामला संविधान के बुनियादी ढाँचे से संबंधित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) 1 और 2

(c) 1 और 3 (d) केवल 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements:

1. Article 22 deals with protection against arbitrary arrest and detention.
2. The Court has declared the A.K.Gopalan vs. State of Madras (1950) case is related to Part III.
3. The Kesavanand Bharati vs. State of Kerala (1974) case deals with the basic structure of the Constitution.

Which of the above statements are correct?

(a) Only 1 (b) 1 and 2

(c) 1 and 3 (d) Only 3

नोट : 25 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'भारतीय संविधान एक गतिशील दस्तावेज है ऐसे में इसका स्वरूप और दायरा बदलता रहा है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका सर्वोपरि रही है।' इस कथन की व्याख्या उदाहरणों की सहायता से कीजिए। (250 शब्द)

'The Indian Constitution is a dynamic document, so its form and scope have been changing, in which the role of the Supreme Court has been paramount.' Explain this statement with the help of examples. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।